

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रम :- प. 10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या./2015 पार्त 25040 जयपुर, दिनांक 20/10/2015

कार्यालय आदेश 35/2015

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश  
दिनांक 18.08.2015 की पालना बाबत।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 की अनुपालना में माननीय न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन महोदय की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 18.08.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. निम्न प्रावधानों के उल्लंघन पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 सपटित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 21 के अन्तर्गत कम से कम 3 माह के लिए अनिवार्य रूप से निलंबित किया जावे :-
  - (i) निर्धारित गतिसीमा से तेज गति में वाहन चलाने तथा ट्रेफिक सिग्नल की लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर।
  - (ii) भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन एवं भार वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर।
  - (iii) नशे में वाहन चलाने पर।
  - (iv) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने पर।
2. हेलमेट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर वाहन चालक/पीछे बैठने वाली सवारी पर जुर्माने के अधिरोपण/ चालान प्रशमन से पूर्व उन्हें कम से कम दो घण्टे की सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं Counseling दी जावे।
3. सीट बेल्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर वाहन चालक/सवारी को जुर्माने के अधिरोपण/चालान प्रशमन से पूर्व उन्हें कम से कम दो घण्टे की सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं Counseling दी जावे।
4. निलंबित किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड संधारित किया जावे एवं निलंबन अवधि के दौरान लाइसेंसधारी को किसी प्रकार की लाइसेंस सम्बन्धित सेवाएं प्रदान नहीं की जावे। इस हेतु कम्प्यूटर पर भी आवश्यक चैक लगाये जावें।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य सरकार को उपरोक्तानुसार की गयी समस्त कार्यवाई की रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु वांछित सूचना निम्न प्रारूप में प्रति माह की सात तारीख तक ई-मेल आई.डी. addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भेजे :-

लाइसेंस निलंबन की जिलेवार रिपोर्ट

प्रारूप - क

जिला :- .....

क्र. सं.	अपराध	नोटिस क्रमांक एवं जारी करने की तिथि	लाइसेंस निलंबन आदेश क्रमांक एवं तिथि	निलंबन अवधि



**सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं काउंसिलिंग की जिलेवार रिपोर्ट**


प्रारूप - ख

जिला :- .....

क्र. सं.	अपराध	चालान संख्या एवं दिनांक	दो घण्टे के सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण एवं काउंसिलिंग की तिथि	चालान प्रशमन तिथि

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में समिति के समक्ष समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
 (गायत्री राठौड़)  
 परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक:- प. 10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या/2015 पार्ट/20040 जयपुर, दिनांक 20/10/2015  
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री एस.डी. बंगा, सचिव, सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, कमरा नं. 222-A, विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 01 को सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (ट्रेफिक) पुलिस, राजस्थान जयपुर को पुलिस विभाग द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर अनुपालना सुनिश्चित कराने एवं संकलित रिपोर्ट प्रति माह 10 तारीख तक परिवहन विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराने बाबत।
3. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
4. अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.) को "सारथी" सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कराने हेतु।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
 अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)



TC/5531  
25/8/15

38

# SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

DT-0  
ATC (R.S.)

**Chairman:** Justice Shri K.S. Radhakrishnan  
**Members:** S. Sundar  
Dr. Nishi Mittal

**Secretary:** SD Banga

BY SPEED POST

MOST IMMEDIATE

F.No.05/2014/CoRS- Part-III

Dated: 18<sup>th</sup> August, 2015

Pl.  
send  
compliance  
timely

250815 To

48  
250815

The Chief Secretary,  
Government of Rajasthan,  
Jaipur  
Email: [cs-rajasthan@nic.in](mailto:cs-rajasthan@nic.in)

**Subject:** ~~Directions~~ to the States/UTs to implement road safety laws – reg.

Sir/Madam,

The Committee constituted by the Supreme Court of India to monitor and measure implementation of road safety laws in the country has had detailed discussions with the concerned Central Ministries and all the States/UTs on the trend of road accidents and fatalities. The data furnished by them have clearly established that the number of fatalities in India continues to be very high, causing serious emotional trauma and economic loss to the families of the deceased and the society. The compensation awarded to the victims by the Insurance Companies also runs into hundreds of crores of rupees every year.

2. The Committee has over the last one year issued directions to the States/UTs to establish institutional arrangements to promote road safety, undertake engineering measures to make roads safe, tighten enforcement together with promoting road safety education and establishing adequate trauma care facilities, and the Committee has been closely monitoring the action being taken by the States/UTs. Even though a number of measures have been taken by the States/UTs as directed by the Committee, the Committee on the basis of detailed analysis of traffic accidents and fatalities has come to the conclusion that unless strong and urgent measures are taken to deal with over speeding, drunken driving, red light jumping, violation of helmet laws and seat belt laws, use of mobile phones while driving, and over loading, the number of accidents and fatalities will continue to remain high.



## SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

-2-

3. The Committee is of the considered view that the States/UTs and their concerned Departments should take stern action against the violators of the law and exercise the discretion under Section 19 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with Rule 21 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 by passing an order disqualifying the offender from holding a driving license for a specified period and also by seeking imprisonment wherever it is provided under the law. The Supreme Court, while constituting the Committee, has also emphasised the necessity of strict and faithful enforcement of all existing laws and norms not only as an absolute principle of law as well as for the high beneficial effects thereof.

4. The Committee, therefore, directs the States/UTs and their concerned Departments to take the following action forthwith:

Suspension of the licence for a period of not less than 3 months under Section 19 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with Rule 21 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for:

- (i) Driving at a speed exceeding the specified limit which in the Committee's view would also include red light jumping;
- (ii) Carrying overload in goods carriages and carrying persons in goods carriages;
- (iii) Driving vehicles under the influence of drink and drugs;
- (iv) Using mobile phone while driving a vehicle.

5. The Committee further directs that in case of driving a vehicle under the influence of drinks or drugs, the police should prosecute the offender and seek imprisonment as prescribed under Section 185 of the Motor Vehicle Act, 1988 even for the first offence.

6. The Committee also directs that the helmet laws be made applicable all over the State/UT both for main riders and the pillion riders. In case where the law relating to the use of helmet is violated by either the main rider or the pillion rider, they should both be subject to Road Safety Education and Counselling for not less than 2 hours before imposition of fine as prescribed under the Act.

7. Those who violate the seat belt law should also be subject to Road Safety Education and Counselling before imposition of fine as mentioned above.

# SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

-3-

8. The Committee further directs the States/UTs to submit Action Taken Reports at the end of every 3 months starting from 1<sup>st</sup> Sept, 2015.

Yours faithfully,



(SD Banga)

Secretary to the Committee

(S. D. BANGA)

Secretary

Committee on Road Safety  
Supreme Court of India

Copy to:

1. Ms Gayatri Rathore, Transport Commissioner & Secretary,  
Government of Rajasthan, Parivahan Bhawan, Sahar Marg, Jaipur  
(Email: transportjaipur14@gmail.com)
2. Shri Hans Kumar Sharma, Additional Transport Commissioner (RS), Govt of  
Rajasthan, Parivahan Bhawan, Sahar Marg, Jaipur (Email:  
transportjaipur14@gmail.com)



(SD Banga)

Secretary to the Committee

(S. D. BANGA)

Secretary

Committee on Road Safety  
Supreme Court of India